

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



रजि.न.34300/80 संख्या 281 श्री विजय पुरम, मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी से, आज लोक निवास, श्री विजय पुरम में दिल्ली दौरे से पहले अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की। बैठक में कानून–व्यवस्था की समीक्षा की गई तथा अफ्रीकन स्वाइन फिवर की रोकथाम और उपचार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, भारत सरकार की स्वीकृति से अग्निवीरों की नियुक्ति दी, राधानगर तट पर एम्बुलेंस वैन तथा एलीफेंटा तट पर रेस्क्यू बोट तैनात करने के निर्देश भी दिए।

शुभकामनाएँ

'दुर्गा पूजा एवं दशहरा' के पावन अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी द्वीपवासियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।



यह पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक हैं तथा हमें सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। माँ दुर्गा की महिषासुर पर तथा भगवान श्रीराम की रावण पर विजय हमें साहस, आस्था और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करने का संदेश देती है।

यह पर्व हमारे सुंदर द्वीपसमूह में विशेष महत्व रखते हैं, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियाँ और परंपराएँ आपसी सद्भाव के साथ फलती–फूलती हैं। द्वीपवासियों में एकजुटता की भावना हमारी साझा पहचान को सुदृढ़ करते हुए एकता, पारस्परिक सम्मान और भाईचारे के बंधनों को सशक्त बनाती है।

आइए, इस पावन अवसर पर हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने, करुणा को बढ़ावा देने तथा 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को सुदृढ़ करने का संकल्प लें। माँ दुर्गा की कृपा से प्रत्येक परिवार में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि आए तथा हमारा द्वीपसमूह एकता, सद्भाव और सतत् विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे।

(डॉ. दिनेश शर्मा)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

अफ्रीकन स्वाइन फीवर की स्थिति एवं रोकथाम के उपायों की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

श्री विजय पुरम, 19 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य पशु रोग आपातकालीन समिति (एसएडीईसी) ने द्वीपों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) की वर्तमान स्थिति तथा इसके प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। बैठक में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की एक टीम ने भाग लिया। इस टीम का नेतृत्व पशुपालन आयुक्त डॉ. नवीन बी. महेश्वरप्पा ने किया।



तीनों ज़िलों के उपायुक्तों ने समिति को वर्तमान स्थिति तथा अब तक किए गए उपायों की जानकारी दी। निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार श्री विजय पुरम के प्रभावित क्षेत्रों में सूअरों को मारने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी, नमूना संग्रह, स्वच्छता एवं रोगाणुशोधन तथा जन–जागरूकता संबंधी गतिविधियों को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

पशुपालन आयुक्त ने जैव–सुरक्षा के कड़े उपायों को अपनाने, संदिग्ध मामलों की समय पर सूचना देने, नियमित निगरानी करने, मृत सूअरों के शवों का सुरक्षित निपटान करने तथा सूअरों और सूअर के मांस एवं उससे बने उत्पादों के अनधिकृत परिवहन को रोकने पर ज़ोर दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक गैर–जूनोटिक रोग है, अर्थात यह मनुष्यों में संक्रमण नहीं फैलाता है।

मुख्य सचिव ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग को अगले तीन महीनों के लिए कीटाणुनाशकों तथा सुरक्षा उपकरणों सहित आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पत्तन प्रबंध बोर्ड, विमानन प्राधिकरणों तथा ज़िला प्रशासन को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और सूअर के मांस एवं उससे बने उत्पादों के परिवहन पर लागू प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए गए।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रशासन ने सूअर पालकों तथा आम जनता से पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ सहयोग करने, निर्धारित जैव–सुरक्षा उपायों का पालन करने तथा सूअरों में बीमारी के लक्षण दिखाई देने या उनकी मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान को सूचित करने की अपील की है।



अर्हक तिथि 01 जनवरी, 2027 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)–2027

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की पात्र मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों से अपील

श्री विजय पुरम, 19 अक्टूबर।

आम जनता एवं राजनीतिक दलों को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अर्हक तिथि 01 जनवरी, 2027 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समय–सारणी घोषित कर दी गई है। इस पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाकर नामावली की शुद्धता एवं समावेशिता सुनिश्चित करना है। इसमें विशेष रूप से उन पात्र नागरिकों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनके नाम अब तक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, साथ ही युवा एवं प्रथम बार मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में छूट गए पात्र मतदाताओं, युवाओं तथा प्रथम बार मतदान करने वाले पात्र नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए विशेष अभियान पहले ही चलाया जा चुका है।

अब 01 जनवरी, 2027 की अर्हक तिथि के संदर्भ में पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने तथा आगामी तीन अर्हक तिथियों अर्थात् 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर, 2027 के लिए अग्रिम आवेदन प्राप्त करने के उद्देश्य से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अंतर्गत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)–2027 आयोजित

शेष पृष्ठ 4 पर

मध्योत्तर अण्डमान में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उपायुक्त ने की बैठक

मायाबंदर, 19 अक्टूबर।

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के उपायुक्त श्री सुशांत पधा ने ज़िले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) की रोकथाम, प्रसार पर अंकुश लगाने तथा रोग के नियंत्रण के लिए तैयारियों की समीक्षा करने और उपायों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने रोग के प्रसार को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों, पंचायती राज संस्थाओं तथा

शेष पृष्ठ 4 पर



मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अण्डमान तथा

पृष्ठ 1 का शेष

किया जा रहा है। इसके तहत मौजूदा निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया जाएगा।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 2027 की समय–सारणी

क्र. सं.	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन	02.11.2026 तक
2.	एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन	**12.11.2026**
3.	दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि	12.11.2026 से 11.12.2026 तक
4.	दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण	28.12.2026 तक
5.	निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन	**04.01.2027**

इस पुनरीक्षण के लिए अर्हक तिथि 01 जनवरी, 2027 निर्धारित की गई है। ऐसे सभी नागरिक, जो निर्धारित अर्हक तिथि को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, यदि उनका नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, तो वे अपना नाम दर्ज़ कराने के लिए आवेदन करें।

इसके अतिरिक्त, ऐसे भावी मतदाता, जो 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर, 2027 की आगामी अर्हक तिथियों के संदर्भ में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, वे भी अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपर्युक्त अर्हक तिथि के संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित कराने के लिए दावा प्रस्तुत करना हो, किसी नाम के सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति दर्ज़ करानी हो अथवा किसी प्रविष्टि में दर्ज़ विवरण के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, तो वह निर्धारित प्रपत्र–6, प्रपत्र–7 अथवा प्रपत्र–8, जैसा भी लागू हो, में अपना दावा या आपत्ति 11 दिसंबर, 2026 तक प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसे सभी दावे एवं आपत्तियाँ संबंधित मतदान केंद्रों पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारियों अथवा बूथ स्तरीय अधिकारियों के पास व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इन्हें डाक द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा जा सकता है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (प्रभारी) द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार दावे एवं आपत्तियाँ ऑनलाइन माध्यम से ECINET ऐप अथवा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। आवश्यक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल–फ्री दूरभाष संख्या 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है। सभी दावे एवं आपत्तियाँ निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 11 दिसंबर, 2026 तक संबंधित प्राधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर युवा एवं प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान अपने नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया है कि वे निर्वाचक नामावली में छूट गए पात्र मतदाताओं, युवाओं तथा प्रथम बार मतदान करने वाले नागरिकों के नाम सम्मिलित कराने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

"मतदाता बनें–निर्वाचक नामावली में अपना नाम सुनिश्चित करें।"

मध्योत्तर अण्डमान में अफ्रीकन स्वाइन फीवर

पृष्ठ 1 का शेष

स्थानीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को कड़ी निगरानी बनाए रखने, संदिग्ध मामलों की तत्काल सूचना देने तथा निर्धारित निवारक उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पशु चिकित्सा विभाग को सूअर पालकों तथा आम जनता के बीच अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लक्षणों, इसके फैलने के तरीकों तथा रोग के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियों के संबंध में जागरूकता गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए। प्रभावित क्षेत्रों से बिना उचित अनुमति के सूअरों तथा सूअर के मांस एवं उससे बने उत्पादों के परिवहन को हतोत्साहित करने और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष ज़ोर दिया गया।

उपायुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं से भी प्रशासन को सक्रिय सहयोग देने की अपील की। उन्होंने ग्राम स्तर पर परामर्श एवं दिशा–निर्देशों का प्रचार–प्रसार करने, सूअर पालकों को जागरूक करने तथा संदिग्ध मामलों की समय पर सूचना देने के लिए पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया। विभागाध्यक्षों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने तथा नामित ज़िला स्तरीय अधिकारियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने आगे ज़ोर दिया कि किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तत्काल पशु चिकित्सा विभाग को दी जानी चाहिए तथा रोग के आगे प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए उचित जैव–सुरक्षा, स्वच्छता एवं रोग नियंत्रण संबंधी उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

बैठक में उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले में पशुधन की सुरक्षा तथा सूअर पालकों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक ज़िम्मेदारी, समय पर सूचनाओं के आदान–प्रदान और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ज़िला प्रशासन ने सभी सूअर पालकों, पशुधन मालिकों तथा आम जनता से सतर्क रहने, आधिकारिक दिशा–निर्देशों का पालन करने और अफ्रीकन स्वाइन फीवर पर नियंत्रण पाने के सामूहिक प्रयासों में संबंधित विभागों को सहयोग देने की अपील की है।

प्रसारण सहायकों के पैनल तैयार करने की प्रक्रिया 27 अक्टूबर को

श्री विजय पुरम, 19 अक्टूबर।

आकाशवाणी श्री विजय पुरम ने प्रसारण सहायक के रूप में पैनल में शामिल किए जाने हेतु आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को सूचित किया है कि पैनल तैयार करने की प्रक्रिया मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2026 को सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में सभी आवेदकों से अनुरोध किया गया है कि वे उक्त प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 27 अक्टूबर, 2026 को सुबह 9.30 बजे आकाशवाणी श्री विजय पुरम में उपस्थित हों।

पशुओं के सस्ते उपचार के लिए 'पशु औषधि विक्रय केंद्र' योजना शुरू

द्वीपों की सहकारी समितियों एवं पीएम–किसान समृद्धि केंद्रों से आवेदन करने का आग्रह

श्री विजय पुरम, 19 अक्टूबर।

भारत सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 'पशु औषधि विक्रय केंद्र' योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य पशुपालकों, विशेषकर ग्रामीण एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराकर पशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। इस पहल के माध्यम से किसानों के उपचार संबंधी खर्च को कम करने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सहित पूरे देश में पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

ये केंद्र पंजीकृत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम–केएसके) तथा सहकारी समितियों द्वारा खोले जा सकते हैं। इसके लिए आवेदकों के पास स्वयं की अथवा किराए की कम से कम 120 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। साथ ही, बी.फार्मा या डी.फार्मा योग्यता प्राप्त पंजीकृत फार्मासिस्ट नियुक्त करना तथा राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से दवा बिक्री का लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक राजस्व खंड में केवल एक केंद्र खोलने की अनुमति होगी। पशुधन की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केंद्र संचालकों को प्रत्येक दवा के कर रहित विक्रय मूल्य पर 20 प्रतिशत का लाभांश मिलेगा। आकांक्षी ज़िलों, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में खोले जाने वाले केंद्रों के लिए एकमुश्त 1.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, केंद्र में रखे गए दवा भंडार तथा दवाओं की खरीद एवं बिक्री की मात्रा के आधार पर प्रतिमाह अधिकतम 20,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।

इन केंद्रों पर केवल भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दवाएं ही बेची जा सकेंगी। सभी बिल आधिकारिक बिक्री केंद्र प्रणाली (प्वाइंट ऑफ सेल प्रणाली) के माध्यम से तैयार करना अनिवार्य होगा। इन केंद्रों पर पारंपरिक पशु चिकित्सा उत्पाद तथा प्रमाणित पशु आहार भी बेचे जा सकेंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना का संयुक्त कार्यान्वयन पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता मंत्रालय तथा भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://pashuaushadhi.dahd.gov.in/ के माध्यम से जमा किए जाने हैं। आवेदन शुल्क 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है, हालांकि आकांक्षी क्षेत्रों में खोले जाने वाले केंद्रों के लिए यह शुल्क माफ है। योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

द्वीपसमूह में पंजीकृत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों तथा सहकारी समितियों से इस पहल में भाग लेने और आवेदन करने का आग्रह किया गया है, ताकि पशु चिकित्सा दवाओं तक किफ़ायती दरों पर पहुंच सुनिश्चित की जा सके तथा पशु स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके।

एथलीट आयोग के चुनावों के लिए IOA की 34 सदस्यीय मतदाता सूची में नीरू, मीराबाई और सिंधु शामिल

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर।

एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट नीरू ढांडा, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को उनके अपने खेल में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एनएसएफ) ने इलेक्टोरल कॉलेज के लिए चुना है। 3 नवंबर को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) के एथलीट कमीशन के सदस्यों के चयन के लिए इन खिलाड़ियों को चुना गया है।

आईओए द्वारा नियुक्त किए गए इलेक्टोरल ऑफिसर संजय के श्रीवास्तव ने शुक्रवार को 34 एथलीट प्रतिनिधियों की सूची जारी की। इलेक्टोरल कॉलेज में 17 एनएसएफ में हर एक से दो नॉमिनी शामिल हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं है। सिंधु और मीराबाई पिछले एथलीट कमीशन का हिस्सा थीं। सितंबर में मंजूर हुए आईओए एथलीट कमीशन नियम के आर्टिकल 10.3 के तहत, हर हिस्सा लेने वाला एनएसएफ सदस्य अपने एथलीट कमीशन के जरिए दो प्रतिनिधिकृ एक पुरुष और एक महिलाकृको नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेटेड एथलीट ऐसे होने चाहिए जो उस खेल का प्रतिनिधित्व करते हों और जिससे आईओए फेडरेशन जुड़ा हो।

राष्ट्रीय एकता दिवस : 31 अक्टूबर को आयोजित होगी 'एकता दौड़'

श्री विजय पुरम, 19 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का खेल एवं युवा कार्य विभाग, प्रशासन के विभिन्न संबंधित विभागों, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी), ज़िला परिषद तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से 31 अक्टूबर, 2026 को शाम 6 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में 'एकता दौड़' का आयोजन करेगा। यह आयोजन भारत के लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। 'एकता दौड़' का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकजुटता तथा आपसी सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देना है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस दौड़ में शिक्षा विभाग तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लगभग 500 विद्यार्थियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह दौड़ नेताजी स्टेडियम से शुरू होगी और कार्बाइंस कोव तक जाकर वापस नेताजी स्टेडियम पहुँचेगी।

खेल एवं युवा कार्य विभाग ने विद्यार्थियों, युवाओं तथा आम जनता से 'एकता दौड़' में उत्साहपूर्वक भाग लेने और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने की अपील की है।

राष्ट्रीय एकता दिवस : 31 अक्टूबर को निकलेगी खुली साइकिल रैली

श्री विजय पुरम, 19 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का खेल एवं युवा कार्य विभाग, भारत के लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए 31 अक्टूबर को खुली साइकिल रैली का आयोजन करेगा।

यह साइकिल रैली सुबह 6 बजे नेताजी स्टेडियम से शुरू होगी, कार्बाइंस कोव तक जाएगी और वहाँ से वापस नेताजी स्टेडियम पहुँचेगी। इस आयोजन का उद्देश्य आम जनता के बीच राष्ट्रीय एकता एवं आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने के साथ–साथ शारीरिक स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन के अंतर्गत 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सभी कार्यालयों, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी), ज़िला परिषद तथा अन्य सहभागी संस्थानों में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की शपथ दिलाई जाएगी। इस शपथ के माध्यम से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार खेल एवं युवा कार्य विभाग ने विद्यार्थियों, युवाओं तथा आम जनता से खुली साइकिल रैली में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है।

एकता के लिए पैडल चलाएँ, अखंडता के लिए साइकिल दौड़ाएँ और एक राष्ट्र की भावना का उत्सव मनाएँ।

व्यावसायिक रसोइयों के कौशल उन्नयन कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 19 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने एवं गति प्रदान करने (आरएएमपी) संबंधी पर्यटन पहलों के अंतर्गत वर्ष 2026–27 के लिए व्यावसायिक रसोइयों के कौशल उन्नयन कार्यक्रम हेतु इच्छुक युवाओं, खानपान प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्तरां तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम के लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण ताज एक्सोटिका, आईएचसीएल तथा टाटा स्ट्राइव के सहयोग से प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय के योजना अनुभाग में जमा किए जा सकते हैं अथवा नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक https://forms.gle/i9iruK1s5fySWfJi7 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2026 को सायं 3 बजे तक है।

जीवनशैली संबंधी रोगों एवं उनके प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आयुर्वेद और योग के दृष्टिकोण पर योग सत्र 2026









श्री विजय पुरम, 19 अक्टूबर।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के अधीन क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), श्री विजय पुरम ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सहयोग से आयुष मंत्रालय और सीआईएसएफ के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी कई पहलें शुरू की हैं।

इस सहयोग के अंतर्गत 14 अक्टूबर, 2026 को सीआईएसएफ इकाई, हैडो घाट पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं योग सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद 15 अक्टूबर, 2026 को सीआईएसएफ इकाई, इस्ट्रैक/इसरो, डॉलीगंज में "जीवनशैली संबंधी रोग एवं उनका प्रबंधन : आयुर्वेद और योग के दृष्टिकोण" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 30 जवानों एवं कर्मियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद) डॉ. आकाश लाल ने जीवनशैली से संबंधित रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन में आयुर्वेद और योग की भूमिका पर प्रकाश डाला।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (आयुर्वेद) डॉ. नताशा सिंह ने जीवनशैली संबंधी रोगों के कारणों, निवारक उपायों एवं प्रबंधन पर जानकारीपूर्ण व्याख्यान दिया। उन्होंने विशेष रूप से मोटापा, उच्च रक्तचाप, संतुलित पोषण तथा तनाव प्रबंधन पर ज़ोर दिया।

योग चिकित्सक डॉ. रोहित कुमार ने विभिन्न योगाभ्यासों एवं श्वास संबंधी अभ्यासों का प्रदर्शन किया तथा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार और तनाव कम करने में इनके लाभों के बारे में बताया।

इन गतिविधियों का उद्देश्य निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देकर, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा आयुर्वेद एवं योग के माध्यम से सीआईएसएफ के जवानों एवं कर्मियों के समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाकर आयुष मंत्रालय और सीआईएसएफ के बीच हुए समझौता ज्ञापन के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना है।

भारत–न्यूजीलैंड एफटीए से किसानों और एमएसएमई के लिए खुलेंगे नए अवसर

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर।

वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लागू होने से भारतीय निर्यात के लिए न्यूजीलैंड में 100 प्रतिशत शुल्क–मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रम–प्रधान क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे।

श्री गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह समझौता भारतीय पेशेवरों के लिए भी नए रास्ते खोलेगा और साथ ही भारत के प्रमुख हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों को फल, सब्जियों, मसालों और अन्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूजीलैंड के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। इसके साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार करने और उनकी आजीविका को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसर भी मिलेंगे।

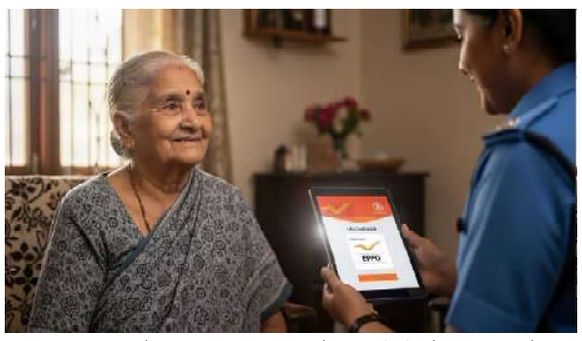
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि डेयरी सहित संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है, ताकि सरकार की नीतियों में किसानों के कल्याण को प्राथमिकता मिलती रहे। गोयल के मुताबिक, न्यूजीलैंड की ओर से भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता भी महत्वपूर्ण है। इससे विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, सेवा क्षेत्र और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही कारोबार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

ईपीएफओ पेंशनधारकों को बड़ी राहत, अब घर बैठे जमा होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक शाखा या ईपीएफओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की मदद से पेंशनधारक घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके तहत डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक पेंशनधारक के घर पहुंचकर पूरी प्रक्रिया में सहायता करेगा।



इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन बुजुर्ग पेंशनधारकों को सहूलियत देना है, जिन्हें चलने–फिरने में परेशानी होती है या जो डिजिटल प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। EPFO के मुताबिक, यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना के ऐसे पेंशनधारकों के लिए उपयोगी है, जिन्होंने अभी तक अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है या जिनके प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने वाली है। प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जमा होने और सत्यापन पूरा होने पर सेवा का खर्च ईपीएफओ की ओर से वहन किया जाता है।

घर पर यह सुविधा प्राप्त करने के लिए पेंशनधारक आईपीपीबी के टोल–फ्री नंबर 033–22029000 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद घर पर डाकिया बुलाने का अनुरोध किया जा सकता है। ईपीएफओ ने पेंशनधारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आईपीपीबी के साथ व्यवस्था की है।

पेंशनधारकों के पास डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का एक और विकल्प है। वे स्मार्टफोन के जरिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में चेहरे की पहचान के माध्यम से पेंशनधारक का सत्यापन किया जाता है, जिससे प्रमाण पत्र जमा करना आसान हो जाता है।

इस सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले पेंशनधारकों को आधार नंबर, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर, पेंशन खाते से जुड़ी जानकारी और मोबाइल नंबर तैयार रखना चाहिए। साथ ही, पेंशन भुगतान एजेंसी के रिकॉर्ड में आधार का पंजीकरण होना भी आवश्यक है।

जीवन प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके जरिए यह प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवित है और उसे पेंशन का भुगतान जारी रखा जाना चाहिए। EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारकों को निर्धारित अवधि पर यह प्रमाण पत्र जमा करना होता है।

यदि पेंशनधारक समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन का भुगतान प्रभावित हो सकता है या रुक सकता है। इसलिए उन्हें अपने पिछले प्रमाण पत्र की तारीख और अगला प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य तौर पर पिछले जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने के एक वर्ष के भीतर नया प्रमाण पत्र देना होता है।

2026 में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनधारक 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं, अन्य पात्र पेंशनधारकों के लिए प्रमाण पत्र जमा करने की सामान्य अवधि नवंबर में रहती है। इनके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित है।

17,500 फीट की ऊंचाई पर एफपीवी ड्रोन्स तैनात करेगी भारतीय सेना, चीन सीमा पर निगरानी होगी और मजबूत

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर।

भारतीय सेना ने 225 फर्स्ट–पर्सन व्यू ड्रोन का एक ऑर्डर दिया है। यह फैसला कड़े मूल्यांकन और कड़े मैदानी परीक्षणों के बाद लिया गया है, जिनमें 17500 फीट तक की अत्यधिक ऊंचाई पर इनका सफल परीक्षण किया गया था। वैसे तो यह ऑर्डर संख्या के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिस कठिन परिस्थिति और ऊंचाई पर इन ड्रोनों का परीक्षण और चयन किया गया है, वह इसे बेहद खास बनाता है। इन ड्रोनों को उनकी सहनशक्ति, सटीकता, रफ्तार और उच्च पहाड़ी इलाकों में काम करने की क्षमता के आधार पर परखा गया है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिक 12000 से लेकर 18000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तैनात हैं।

हिमालय और सियाचिन ग्लेशियर जैसे इन इलाकों में अत्यधिक ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से न सिर्फ इंसानी क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि पारंपरिक उपकरण भी ठीक से काम नहीं कर पाते। ऐसे में दूर–दराज की इन चौकियों पर रसद और सामान पहुंचाने के लिए पारंपरिक रूप से पैदल सैनिकों, खच्चरों या पुराने हो चुके चीता हेलीकॉप्टरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

हालांकि, हेलीकॉप्टरों से सामान पहुंचाना महंगा, मौसम पर निर्भर और धीमा होता है। ऐसे में ड्रोन एक तेज, किफायती और सुरक्षित विकल्प बनकर उभरे हैं। सेना पहले ही 'अश्नी प्लाटून' जैसी छोटी सामरिक इकाइयों से लेकर बड़े 'बैटलफील्ड एयर सपोर्ट' बटालियनों तक एक लेयर्ड ड्रोन रणनीति तैयार कर चुकी है।



दूसरी ओर, यह सब इतना आसान भी नहीं है। समुद्र तल से 15000 फीट की ऊंचाई पर हवा का घनत्व लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है। इसकी वजह से ड्रोन के पंखों को पकड़ने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिलती, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट काफी कम हो जाता है। बात यही तक खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कई बड़ी तकनीकी मुश्किलें सामने हैं। इसको ऐसे समझिए कि हवा कम होने के कारण मोटरों को ठंडक नहीं मिलती, जिससे वे भारी लोड के कारण जल्दी गर्म होकर जल सकती हैं।

इसके अलावा कड़ाके की ठंड में लिथियम–आधारित बैटरियां धीमी हो जाती हैं। समुद्र तल पर जो बैटरी 6 मिनट का फ्लाइट टाइम देती है, वही ऊंचाई पर मात्र 2 से 3 मिनट ही टिक पाती है। इसलिए उड़ान भरने से पहले बैटरियों को गर्म करना और हवा में उन्हें इंसुलेट रखना पड़ता है। गौरतलब है कि इन सभी चुनौतियों से पार पाने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के स्पीति जैसे दुर्गम इलाकों में घरेलू ड्रोन निर्माताओं के साथ मिलकर काम किया है। इन परीक्षणों के आधार पर सेना ने कई स्वदेशी उत्पादों को शॉर्टलिस्ट किया है।

डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं के विज्ञापन पर सख्ती की तैयारी, औषधि नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा अधिसूचित

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (हि.स.)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापन को लेकर नियम सख्त करने की तैयारी की है। इसके तहत दवा निर्माता कंपनियों के साथ–साथ खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और वितरकों पर भी विज्ञापन संबंधी प्रतिबंध लागू करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस कदम का उद्देश्य बिना अनुमति दवाओं के प्रचार पर रोक लगाना और लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना दवाओं के इस्तेमाल से होने वाले संभावित नुकसान से बचाना है।

मंत्रालय ने इस संबंध में औषधि नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा अधिसूचित किया है। 28 सितंबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 861(ई) के तहत नियम 65 में नया उपनियम (22) जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। यह संशोधन फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर है और इस पर संबंधित पक्षों से सुझाव व आपत्तियां मांगी गई हैं।

मौजूदा नियमों के तहत शेड्यूल एच, एच1 और एक्स में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए दवा निर्माताओं को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है। हालांकि, इन दवाओं की खुदरा और थोक बिक्री करने तथा वितरण का लाइसेंस रखने वाले कारोबारियों पर विज्ञापन संबंधी प्रतिबंध स्पष्ट रूप से लागू नहीं थे।

प्रस्तावित संशोधन के बाद इन श्रेणियों की दवाओं को बेचने, स्टॉक रखने, प्रदर्शित करने, बिक्री के लिए पेश करने या वितरित करने का लाइसेंस रखने वाले प्रतिष्ठानों पर भी यह पाबंदी लागू होगी। ऐसे कारोबारी केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना संबंधित दवाओं का विज्ञापन नहीं कर सकेंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस पहल से दवाओं की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में नियामकीय निगरानी मजबूत होगी। साथ ही, ऐसे प्रचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, जो लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना दवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

शेड्यूल एच, एच1 और एक्स में ऐसी दवाएं शामिल हैं, जिनके इस्तेमाल में चिकित्सकीय निगरानी जरूरी होती है। इनमें कुछ एंटीबायोटिक, मनःप्रभावी दवाएं और अन्य नियंत्रित दवाएं शामिल हैं। इनका अनुचित इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

मंत्रालय ने यह प्रस्ताव औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की 93वीं बैठक की सिफारिशों के बाद तैयार किया है। बोर्ड की बैठक 16 फरवरी 2026 को हुई थी। इसमें दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाले कारोबारियों के विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों की जरूरत पर विचार किया गया था।

मंत्रालय ने मसौदा नियमों पर आम जनता और संबंधित पक्षों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं। राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सुझाव भेजे जा सकेंगे। निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार संशोधन को अंतिम रूप देने पर निर्णय लेगी।

आईआरएस अधिकारी एकता विश्नोई ने अमरीका में तीन स्वर्ण पदक जीते

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर

एकता विश्नोई ने अमरीका में वर्ल्ड मास्टर्स क्लासिक और इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में 362.5 किलोग्राम के संयुक्त भार के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने स्क्वाट में 130 किलोग्राम, बेंच प्रेस में 72.5 किलोग्राम और डेडलिफ्ट में 160 किलोग्राम भार उठाकर कनाडा और जापान की प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। विश्नोई ने तीनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी सुश्री विश्नोई ने इससे पहले फिट इंडिया मिशन का नेतृत्व किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण की उप महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

NEET-JEE की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई, छात्रों को मॉक टेस्ट और परफॉर्मेंस एनालिसिस में मिलेगी मदद

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पढ़ाई के विकल्प लगातार बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में 'अभ्यास AI' को लेकर छात्रों के बीच चर्चा है। हालांकि, इसके नए संस्करण या किसी आगामी लॉन्च की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नेशनल टेस्ट अभ्यास प्लेटफॉर्म पहले से ही मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करता है।

नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप पर हिंदी और अंग्रेजी में मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। इससे उन छात्रों को भी मदद मिल सकती है, जो अपनी सुविधा के अनुसार भाषा चुनकर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। ऐप के जरिए छात्र मोबाइल या टैबलेट पर अभ्यास कर सकते हैं और टेस्ट पूरा करने के बाद अपना परिणाम देख सकते हैं।

NTA के नेशनल टेस्ट अभ्यास प्लेटफॉर्म पर NEET-UG और JEE Main की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक परीक्षा जैसे माहौल में अभ्यास करने का अवसर देना है। छात्र टेस्ट देकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उन्हें किन विषयों में अधिक मेहनत करने की जरूरत है।

इस प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण की मदद से छात्रों को उनके प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी मिलती है। इससे सवाल हल करने में लगने वाले समय, गलतियों और समय प्रबंधन जैसी बातों को समझने में सहायता मिल सकती है। इस तरह छात्र अपनी तैयारी की कमजोरियों को पहचानकर उनमें सुधार करने की योजना बना सकते हैं।

NEET और JEE की तैयारी कर रहे छात्र फिलहाल NTA के आधिकारिक नेशनल टेस्ट अभ्यास प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए NTA की वेबसाइट nta.ac.in/abhyas पर जानकारी उपलब्ध है। छात्रों को किसी नए संस्करण, अतिरिक्त सुविधा या लॉन्च की तारीख से संबंधित दावों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक घोषणा की जांच करनी चाहिए। एआई आधारित प्लेटफॉर्म अभ्यास और प्रदर्शन का विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए नियमित पढ़ाई, NCERT की समझ, प्रश्नों का अभ्यास और समय–समय पर रिवीजन भी जरूरी है।

डीजीसीए का बड़ा फैसला, पावरबैंक के एक विशिष्ट मॉडल पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो विमान में आग लगने की एक घटना के बाद मोबिकिन्स एमके–पीबी–04 पावरबैंक को भारत आने–जाने वाली और देश के भीतर संचालित होने वाली सभी उड़ानों में ले जाने या परिवहन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विमानन नियामक ने यह निर्देश उस घटना के बाद जारी किया, जिसमें रविवार को दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक उड़ान में इस पावरबैंक से जुड़ी आग लगने के कारण विमान को हैदराबाद की ओर मोड़ना पड़ा था।

इसके बाद डीजीसीए प्रमुख वीर विक्रम यादव ने एयरलाइंस को निर्देश दिया कि इस विशेष पावरबैंक मॉडल को न तो यात्रियों द्वारा विमान में लाया जाए और न ही कार्गो के रूप में इसका परिवहन किया जाए। आदेश के तहत एयरलाइंस को प्रभावित डिवाइस की पहचान करने, उसे उड़ानों में लाए जाने से रोकने और यात्रियों को उचित माध्यमों से सुरक्षा संबंधी सलाह जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह प्रतिबंध केवल मोबिकिन्स एमके–पीबी–04 मॉडल पर लागू होगा और सभी पावरबैंकों पर सामान्य प्रतिबंध नहीं है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपने पावरबैंक का मॉडल नंबर जांचने और एयरलाइंस के दिशा–निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। जिन लोगों के पास यह विशेष मॉडल है, उन्हें भारत के भीतर या भारत आने–जाने वाली किसी भी उड़ान में इसे साथ नहीं ले जाने को कहा गया है।

यह कदम लिथियम–आयन बैटरियों और पावरबैंकों से जुड़े सुरक्षा नियमों को और कड़ा किए जाने के बाद उठाया गया है। डीजीसीए के मौजूदा खतरनाक वस्तु दिशा–निर्देशों के अनुसार, पावरबैंक और अतिरिक्त बैटरियां केवल हैंड बैगेज में ही ले जाई जा सकती हैं और इन्हें ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखने की अनुमति नहीं है। नियामक ने यात्रियों को उड़ान के दौरान पावरबैंक की मदद से मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करने से भी रोक दिया है। विमान की सीटों पर उपलब्ध पावर आउटलेट के माध्यम से भी ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी। एयरलाइंस को यात्रियों को इन नियमों के बारे में जागरूक करने, केबिन क्रू को बैटरी से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने और लिथियम बैटरी में आग लगने या खराबी की किसी भी घटना की जानकारी नियामक को देने के निर्देश दिए गए हैं।

इतिहास के पन्नों में 20 अक्टूबर : 1962 में चीन ने भारत पर किया हमला

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (हि.स.)।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ने 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध का रूप ले लिया। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने लद्दाख और तत्कालीन उत्तर–पूर्व सीमा क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर व्यापक हमले किए। करीब एक महीने तक चले इस संघर्ष में भारत को भारी सैन्य क्षति उठानी पड़ी। युद्ध की प्रमुख वजह पश्चिमी क्षेत्र में अक्साई चिन और पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद था। संघर्ष के दौरान चीनी सेना ने तवांग और वालोंग सहित पूर्वोत्तर के कई इलाकों में बढ़त हासिल की। वहीं, लद्दाख में भी भारतीय सेना को कठिन परिस्थितियों में मुकाबला करना पड़ा।

दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, कड़ाके की ठंड और सैन्य संसाधनों की कमी ने भारतीय जवानों की चुनौतियां बढ़ा दीं। इसके बावजूद उन्होंने कई मोर्चों पर अदम्य साहस का परिचय दिया। 20 नवंबर 1962 को चीन ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की, जो 21 नवंबर से प्रभावी हुआ। इस युद्ध ने भारत की रक्षा तैयारियों की कमजोरियों को उजागर किया। इसके बाद देश ने सैन्य क्षमता बढ़ाने, हथियारों और उपकरणों की उपलब्धता सुधारने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। 1962 का युद्ध भारतीय इतिहास की ऐसी निर्णायक घटना बना, जिसने देश की रक्षा नीति को नई दिशा दी।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1568– अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया।

1740– मारिया थेरेसा आस्ट्रिया, हंगरी और बोहमिया की शासक बनी।

1774– कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) भारत की राजधानी बनी।

1803– अमेरिकी सीनेट ने फ्रांस से लुइसियाना क्षेत्र की खरीद को मंजूरी दी, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका का आकार दोगुना हो गया।

1822– लंदन संडे टाइम्स का पहला अंक प्रकाशित।



1880– एम्सटर्डम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना।

1904– चिली और बोलविया ने शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षकर किया।

1905– रूस में 11 दिन तक चले ऐतिहासिक हड़ताल की शुरुआत हुई।

1946– वियतनाम की डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सरकार ने 20 अक्टूबर को वियतनाम महिला दिवस के रूप में घोषित किया।

1947– अमेरिका और पाकिस्तान ने पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित किये।

1963 – दक्षिण अफ्रिका में नेल्सन मंडेला और आठ अन्य के खिलाफ मामला शुरु।

1970 – सैयद बर्रे ने सोमालिया को समाजवादी राज्य घोषित किया।

1991 – भारत के उत्तरकाशी में 6.8 तीव्रता के भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत।

1995 – संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष स्वर्ण जयंती अधिवेशन आरम्भ।

1995 – श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर शारजाह कप फाइनल ट्रॉफी अपने नाम किया।

1998 – मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम पांचवी बार पुनः राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित।

जन्मदिन विशेषः मैनुअल फ्रेडरिक, ओलंपिक मेडल जीतने वाले केरल के पहले खिलाड़ी

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)।

मैनुअल फ्रेडरिक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी थे। वह उस दौर में खेले जब भारतीय हॉकी का पूरे विश्व में दबदबा था। बतौर गोलकीपर खेलने वाले फ्रेडरिक 1972 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। मैनुअल फ्रेडरिक का जन्म 20 अक्टूबर, 1947 को केरल के कन्नूर शहर में हुआ था। फ्रेडरिक का खेल में सफर तब शुरू हुआ जब उन्हें बेंगलुरु में आर्मी की स्कूल टीम में भर्ती किया गया। हॉकी से पहले वे कन्नूर में फुटबॉल खेलते थे।

उन्होंने 1971 में इंडिया के लिए डेब्यू किया और सात साल तक नेशनल टीम के लिए खेले। फ्रेडरिक ने दो हॉकी वर्ल्ड कप दृ नीदरलैंड्स (1973) और अर्जेंटीना (1978) में भी देश का प्रतिनिधित्व किया। नीदरलैंड में आयोजित हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। उनके करियर का सबसे अहम समय 1972 में म्यूनिख में आयोजित ओलंपिक था। भारतीय टीम ने इस ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था।

फ्रेडरिक केरल राज्य से ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। ओलंपिक मेडल जीतने वाले दूसरे केरलवासी पी. आर. श्रीजेश हैं, जिन्होंने 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। केरल के लिए दोनों



मेडल नेशनल हॉकी टीम के गोलकीपरों ने जीते हैं।

फ्रेडरिक का क्लब करियर भी काफी सफल रहा था। उन्होंने कर्नाटक में एएससी और एचएएल के साथ–साथ सर्विसेज, उत्तर प्रदेश और मशहूर मोहन बागान क्लब का प्रतिनिधित्व किया। अपनी बेहतरीन और साहसिक गोलकीपिंग फ्रेडरिक अपने दोस्तों और टीम के साथी खिलाड़ियों के बीच 'टाइगर' के नाम से मशहूर थे। उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक को बचाने में महारत हासिल की थी। भारतीय खेलों में फ्रेडरिक के शानदार योगदान को देखते हुए उन्हें 2019 में मेजर ध्यानचंद अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। 31 अक्टूबर 2025 को 78 वर्ष की आयु में उनका निधन बेंगलुरु में हुआ था।–आईएएनएस

परियोजना निदेशक का कार्यालय
अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी (अ.नि.ए.नि.सो.)

विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम, 2026 के लिए ऑर्केस्ट्रा/म्यूजिकल बैंड समूहों से कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित

F. No. 3-5/ANACS/PROC/IEC/GS/2026-27/821 Dt. 19.10.2026

अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी (ANACS) द्वारा विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में **12 दिसंबर, 2026** को एक ऑर्केस्ट्रा/म्यूजिकल बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तय हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के माध्यम से एचआईवी/एड्स (HIV/AIDS) के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही, इसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स से जुड़े कलंक और भेदभाव को मिटाने, रोकथाम, करुणा और जागरूकता के संदेशों को फैलाने में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

इस संबंध में, उक्त कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति देने के इच्छुक ऑर्केस्ट्रा/म्यूजिकल बैंड समूहों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इच्छुक ऑर्केस्ट्रा/म्यूजिकल बैंड समूहों से अनुरोध है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर शाम 4.00 बजे तक अपने आवेदन **परियोजना निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी, रेड रिबन बिल्डिंग, अटलांटा प्वाइंट, श्री विजय पुरम** के कार्यालय में जमा करें। संगीतमय प्रस्तुति की न्यूनतम अवधि दो (2) घंटे की होनी चाहिए।

ऑर्केस्ट्रा/म्यूजिकल बैंड समूहों का चयन अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की क्रय समिति (Purchase Committee) द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तों और पात्रता मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन जमा करने से पहले पात्रता आवश्यकताओं, नियमों और शर्तों तथा अन्य प्रासंगिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

विस्तृत नियम और शर्तें, पात्रता मानदंड, आवेदन की आवश्यकताएं और अन्य प्रासंगिक जानकारी अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट www.anacs.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध हैं।

आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए इच्छुक आवेदक **श्री कौशिक कुमार हलदर, सहायक निदेशक (IEC) फोनः 9474281620 और श्री आसिफ रेहान, प्रशासनिक अधिकारी फोन नंबर : 9531810524** पर संपर्क कर सकते हैं।

खरीद अधिकारी (आइ/सी)

ई–निविदा सूचना

F.No. M/82/2026-O/o Sr Mrg (TSM)-ANIIDCO-AN/3906 दिनांक 12.10.2026

डॉल्फिन रिसॉर्ट, स्वराज द्वीप के लिए रसोई उपकरण हुड और निकास प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना और चालू करने के लिए अनुबंध के लिए ऑनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा के नियम और शर्तों युक्त दस्तावेज वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा प्रबंधक, (पर्यटन), अनिडको, विकास भवन, श्री विजय पुरम से भी सभी कार्य दिवसों के दौरान दिनांक 02/11/2026 के सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा दिनांक 03/11/2026 को पूर्वाहन 11.00 बजे तक या उससे पहले ऑनलाइन (https://eprocure.andamannicobar.gov.in) पर भरी जानी चाहिए और दस्तावेज मुहरबंद लिफाफे में रखकर निगमित कार्यालय स्थित टेंडर बॉक्स में दिनांक 03/11/2026 को दोपहर 12.00 बजे तक डाल दें। तकनीकी बोली उसी दिन सायं 4.00 बजे निविदादाताओं या उनके अधि.त प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा।

निगम के महाप्रबंधक (पर्यटन) के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा सभी को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यटन), अनिडको

शपथ पत्र

मैं, टी. जे. शेहनाज़ (T J Shehnaz), पत्नी सी. हुसैन मोहम्मद (C Hussain Mohammed), पुत्री ताजुद्दीन (Thajudeen), निवासी होप टाउन (Hope Town), सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन एवं घोषणा करती हूँ :

1. यह कि मेरा नाम टी. जे. शेहनाज़ (T J Shehnaz) है, जिसे पूर्ण रूप से ताजुद्दीन जमीला शेहनाज़ (Thajudeen Jameela Shehnaz) लिखा और पढ़ा जाता है।
2. यह कि मेरे पासपोर्ट में मेरी माता का नाम त्रुटिवश अबू कारतीथ जमीला (Aboo Kartieth Jameela) दर्ज हो गया है, जबकि उनका सही नाम अबू कटियाथ जमीला (Aboo Katiath Jameela) है।
3. यह कि अबू कारतीथ जमीला (Aboo Kartieth Jameela) और अबू कटियाथ जमीला (Aboo Katiath Jameela) दोनों एक ही और एक ही व्यक्ति हैं।
4. मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे पासपोर्ट (पासपोर्ट संख्या P7088787) में दर्शाया गया मेरी माता का नाम गलत है और इसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है।
5. उपरोक्त घोषणा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और यह मेरे पासपोर्ट में मेरी माता के नाम में सुधार के उद्देश्य से की गई है। इसके अलावा, यदि उपरोक्त घोषणा में दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है, तो मैं किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँगी।

शपथकर्ता

भारत की गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट के पार

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। भारत ने गैर–जीवाश्म ईंधन से संचालित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें 2025–26 के दौरान 55 गीगावाट से अधिक की वृद्धि शामिल है। केंद्र सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा पर निर्भरता के अपने दृष्टिकोण को और सौर तथा पवन ऊर्जा को प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में रेखांकित किया है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए कुछ आंकड़े भी साझा किए। सरकार ने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सीईए ने 2031–32 तक लगभग 74 गीगावाट भंडारण क्षमता का अनुमान लगाया है।

इसमें पंप स्टोरेज परियोजनाओं – पीएसपी से लगभग 27 गीगावाट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों – बीईएसएस से 47 गीगावाट से अधिक शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने पीएसपी के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए समन्वित नीतिगत, नियामक, मांग–पक्ष और आपूर्ति–पक्ष उपायों की एक श्रृंखला भी अपनाई है। इन उपायों में नीतिगत स्पष्टता, वित्तीय सहायता, मंजूरी की सरल प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी खरीद और एकीकृत ग्रिड योजना शामिल हैं।

मोबाइल पर लाइव रहेगी सरकार, कृषि मंत्री ने किसानों को समर्पित किया नया पोर्टल

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को संशोधित एग्री वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य किसानों तक सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और खेती से जुड़ी सटीक जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराना है। इससे किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन के लिए अलग–अलग कार्यालयों तथा वेबसाइटों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।



श्री चौहान ने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि सरकार हर समय आम नागरिकों और किसानों के लिए मोबाइल पर उपलब्ध रहे। तकनीक की सार्थकता तभी है जब उसका लाभ सीधे खेत–खलिहान तक पहुंचे और किसानों का जीवन आसान बने।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पोर्टल की सफलता सही और समयबद्ध जानकारी से तय होगी। पुरानी या अधूरी सूचनाएं व्यवस्था पर भरोसा कम करती हैं, इसलिए पोर्टल पर हर जानकारी का लगातार अपडेट होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही भाषा और प्रक्रिया को इतना सरल रखा जाए कि कम पढ़े–लिखे छोटे और सीमांत किसान भी इसे आसानी से समझ एवं चला सकें। किसानों को इस पोर्टल और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल में माहिर बनाने के लिए देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए एक विशेष प्रशिक्षण अभियान भी चलाया जाएगा।

यह नया पोर्टल इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के डीबीआईएम 3.0 और जीआईजीडब्ल्यू 3.0 मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जो बेहद सुरक्षित, मोबाइल–अनुकूल और दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए भी पूरी तरह सुलभ है। यह मंच पीएम–किसान, एग्रीस्टैक और पीएम फसल बीमा योजना जैसी बड़ी पहलों के लिए एक साझा प्रवेश–द्वार का काम करेगा।

इस पोर्टल में किसानों को सब कुछ एक ही जगह पर सूचनाएं मिल जाएंगी। मसलन मंत्रालय की सभी योजनाएं, सब्सिडी, नियम और डिजिटल सेवाएं अब एक ही पोर्टल पर मौजूद हैं जिससे समय और भागदौड़ की पूरी बचत होगी। ऑनलाइन पात्रता जांच, सीधे आवेदन और खाते में सहायता राशि पहुंचने से प्रक्रिया पारदर्शी होगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर इसे बेहद हल्का और यूजर–फ्रेंडली बनाया गया है जो साधारण स्मार्टफोन और कमजोर नेटवर्क में भी आसानी से काम करता है।

इसके साथ ही समय पर सही मौसम की जानकारी भी मिलेगी। जैसे मौसम का हाल, नई वैज्ञानिक खेती के तरीके, बीज–खाद की उपलब्धता और मंडियों के भाव की प्रामाणिक जानकारी सीधे किसान तक पहुंचेगी। दिव्यांगजनों के लिए भी सुगम होगा। आधुनिक सरकारी मानकों के तहत इसे ऐसा बनाया गया है कि दृष्टिबाधित और दिव्यांग भाई–बहन भी स्क्रीन–रीडर और सरल नेविगेशन से इसका लाभ उठा सकेंगे।

इसरो को बड़ी सफलता, अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने का परीक्षण सफल

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (हि.स.)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के दो हिस्सों को अलग करने से जुड़े कई परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन परीक्षणों से यह जांचा गया कि अंतरिक्ष में जरूरी समय पर क्रू मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से सुरक्षित तरीके से अलग किया जा सकता है या नहीं। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाले भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में अहम मानी जा रही है। ये परीक्षण तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किए गए।



गगनयान का पहला मानवरहित मिशन जी1 साल 2026 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल उड़ान के दौरान एक साथ जुड़े रहेंगे। मिशन के दौरान दोनों हिस्से मिलकर काम करेंगे और उनके बीच बिजली तथा दूसरी जरूरी सेवाओं का संपर्क बना रहेगा। हालांकि, जब अंतरिक्ष यान को धरती पर लौटना होगा, तब क्रू मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से अलग करना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया में कई उपकरण काम करेंगे। किसी भी तरह की खराबी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी को प्रभावित कर सकती है।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष यान के दोनों हिस्सों को जोडक़र अलग करने की प्रक्रिया की जांच की गई। इस दौरान यह भी देखा गया कि अलग होते समय लगने वाले झटकों का जरूरी उपकरणों पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता। इनमें दिशा बताने वाली प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गर्मी से बचाने वाली परत और तापमान नियंत्रित करने वाले सिस्टम शामिल हैं। इनकी सही कार्यक्षमता मिशन के लिए जरूरी है। बता दें गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी पर लौटना है, जबकि सर्विस मॉड्यूल अंतरिक्ष में जरूरी सेवाएं देता है।

गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और सुरक्षित वापस लाने की योजना है। इसरो का लक्ष्य पहले बिना यात्रियों वाला जी1 मिशन 2026 में भेजना है। ऐसे मिशनों से अंतरिक्ष यान के अलग–अलग उपकरणों और सुरक्षा प्रणालियों की जांच की जाएगी। इन परीक्षणों से मिले नतीजे आगे की तैयारियों में मदद करेंगे। मानव सहित उड़ान से पहले अंतरिक्ष यान की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे अहम है।

मेटा को सरकार का निर्देश, फेसबुक और इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशन सिस्टम की करे समीक्षा

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंटेंट रिकमेंडेशन और रैंकिंग सिस्टम की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में सोशल मीडिया एल्गोरिद्म किस तरह जानकारी को बयावा देते हैं, इसे लेकर सरकार ने अपनी निगरानी और सख्त कर दी है।

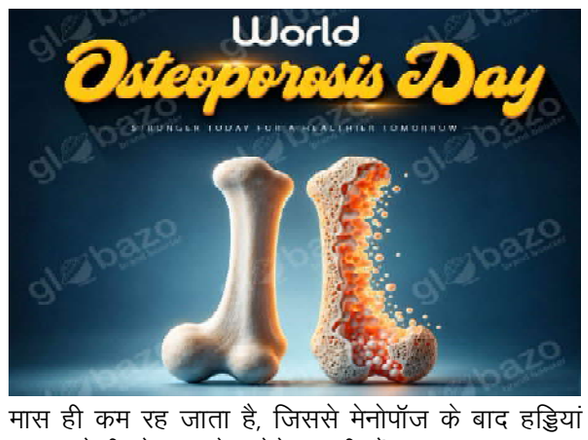
मंत्रालय द्वारा जारी एक एडवाइजरी में मेटा से कहा गया है कि उसकी रिकमेंडेशन प्रणाली ऐसी न हो, जिससे उपयोगकर्ताओं के सामने केवल एक या सीमित प्रकार की विचारधाराएं या कथानक बार–बार प्रस्तुत हों। इसके बजाय लोगों को विविध, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी तक अधिक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने मेटा को ऐसे कंटेंट की पहचान, समीक्षा और त्वरित निगरानी के लिए तंत्र मजबूत करने का भी निर्देश दिया है, जो रिकमेंडेशन सिस्टम के जरिए तेजी से बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच रहा हो और जिससे सार्वजनिक भ्रम, हिंसा या कानून–व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।

इसके अलावा, अमेरिकी कंपनी को इन उपायों को तत्काल लागू करने और उठाए गए कदमों की जानकारी सरकार को देने के लिए भी कहा गया है। एडवाइजरी में विशेष रूप से सार्वजनिक घटनाओं से जुड़ी तस्वीरों, वीडियो और ग्राफिक्स का उल्लेख किया गया है, जिनकी प्रामाणिकता, समय, स्थान या परिस्थितियों को लेकर अस्पष्टता हो सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे मामलों में अतिरिक्त संदर्भ उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जहां पुराने या असंबंधित दृश्य वर्तमान घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किए जाएं, वीडियो को चुनिंदा रूप से संपादित किया गया हो या आपात स्थिति, पुलिस कार्रवाई अथवा अन्य सरकारी उपायों को लेकर अपुष्ट दावे किए जा रहे हों। यह कदम मेटा की कंटेंट मॉडरेशन और रिकमेंडेशन प्रणालियों को लेकर सरकार की बयती निगरानी का ताजा उदाहरण माना जा रहा है। इससे पहले अगस्त में सरकारी अधिकारियों ने मेटा के अधिकारियों से कंटेंट रिकमेंडेशन एल्गोरिद्म, डीपफेक, सिंथेटिक मीडिया और गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल किए थे। मेटा ने हाल ही में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को लेकर उठी चिंताओं के बाद कंटेंट और विज्ञापन संबंधी सुरक्षा उपायों को भी और मजबूत किया है। –आईएएनएस

'वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे': 50 की उम्र के बाद हर तीसरी महिला को क्यों है ऑस्टियोपोरोसिस, जानें इसके पीछे की वजहें

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। अक्सर बुजुर्ग महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या देखने को मिलती है। एक आंकड़े के मुताबिक, 50 से अधिक उम्र के हर तीसरी महिला इस बीमारी का शिकार है, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 5 में से 1 का है। यह अनुपात स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह बीमारी महिलाओं के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है।



हर साल 20 अक्तूबर को 'वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे' मनाया जाता है, इसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां अपने घनत्व और मजबूती को तेजी से खोने लगती हैं, और सरल शब्दों में कहें तो हड्डियां धीरे–धीरे गलने लगती हैं, जिससे वे बहुत कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। यही वजह है कि कुछ बुजुर्ग महिलाओं को एक मामूली सी ठोकर या गिरने पर भी कूल्हे, रीढ़ की हड्डी या कलाई में फ्रैक्चर हो जाता है।

यह बीमारी अक्सर 'साइलेंट किलर' कहलाती है, क्योंकि इसके लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक पहला फ्रैक्चर न हो जाए। महिलाओं में कुछ हार्मोनल बदलाव की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा अधिक होता है साथ ही उनकी जीवनशैली से जुड़ी कुछ गलतियां भी इस बीमारी के जोखिम को बढ़ा देती हैं। हर महिला के लिए इन कारणों को जानना और समझना बहुत जरूरी है।

महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा कारण मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में आने वाली तेजी से कमी है। एस्ट्रोजन हार्मोन हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करता है। यह हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाओं को सक्रिय रखता है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का स्तर अचानक गिर जाता है, जिससे हड्डी के नुकसान होने की दर तेजी से बढ़ जाती है।

महिलाओं के जीवनचक्र में गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान शरीर को बच्चे के विकास के लिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर मां अपनी डाइट में पर्याप्त कैल्शियम नहीं ले रही है, तो शरीर बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए मां की हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है।

महिलाओं में हड्डियों का अधिकतम घनत्व पुरुषों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कम होता है। पीक बोन मास 20 से 30 वर्ष की आयु तक बनता है। यदि बचपन और किशोरावस्था में पोषण (खासकर कैल्शियम और विटामिन डी) और व्यायाम पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, तो उनका शुरुआती बोन मास ही कम रह जाता है, जिससे मेनोपॉज के बाद हड्डियां ज्यादा तेजी से कमजोर होने लगती हैं।

महिलाओं को अपनी हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए 40 की उम्र से ही सचेत हो जाना चाहिए। उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार लेना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम जैसे तेज चलना, हल्का दौड़ना या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये व्यायाम हड्डियों के निर्माण को गति देते हैं।

एशियन पैरा गेम्स 2026 में मोना अग्रवाल ने जीता गोल्ड मेडल, फाइनल में रचा इतिहास

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है. महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मोना अग्रवाल ने जबरदस्त वापसी करते हुए गोल्ड मेडल जीता. मोना ने फाइनल में 250 का स्कोर करके गोल्ड मेडल जीता. इस इवेंट में भारत को दोहरी खुशी मिली है, क्योंकि सिल्वर मेडल भी भारत की अवनी लेखरा ने जीत लिया है. अवनी का स्कोर 249.6 रहा.

इससे पहले मोना अग्रवाल क्वालीफिकेशन राउंड के भी टॉप पर रही थीं. उन्होंने क्वालीफिकेशन में 629.1 का स्कोर करके एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड बना डाला था. वहीं क्वालीफिकेशन में अवनी लेखरा दूसरे स्थान पर रही थीं. भारतीय शूटरों ने क्वालीफिकेशन वाला प्रदर्शन फाइनल में भी दोहराया और गोल्ड के साथ–साथ सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया.

मोना अग्रवाल के लिए यह गोल्ड मेडल ऐतिहासिक है, क्योंकि स्टेज 2 सीरीज 2 के बाद वह पांचवें स्थान पर चल रही थीं. वहीं अवनी लेखरा शुरू से ही बढ़िया लय में चल रही थीं. मगर आखिरी कुछ शॉट्स में मोना अग्रवाल ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए 250 का स्कोर करके गोल्ड मेडल जीत लिया. मोना और अवनी, दोनों ने 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है.



एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली मोना अग्रवाल का जन्म राजस्थान के सीकर में हुआ था. उन्हें केवल 9 महीने की उम्र में पोलियो ने अपनी चपेट में ले लिया था. इसने उनके दोनों पैरों पर प्रभाव डाला. पैरा शूटिंग में आने से पहले मोना पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग और वीमेंस सिटिंग वॉलीबॉल में भी हाथ आजमाए थे. मोना अगरवाल 2024 पैरालंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहीं और इसी साल पैरा शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर आई हैं. दूसरी ओर अवनी लेखर 2020 टोक्यो और 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रही थीं. ओलंपिक चैंपियन अवनी को इस बार अपनी हमवतन शूटर के हाथों हार झेलनी पड़ी.

106 युवा कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि विकसित भारत का सपना केवल अच्छे बुनियादी ढांचे और भौतिक विकास से साकार नहीं हो सकता, बल्कि इसमें कला, संस्कृति और विरासत की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा और सच्ची पहचान उसकी सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत में निहित है। श्री शेखावत ने कहा कि देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विश्व स्तर पर इसकी पहचान और प्रतिष्ठा को मान्यता भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने ने उन पीढ़ियों के कलाकारों के योगदान को याद किया जिन्होंने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को कायम रखा है। श्री शेखावत ने संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2024 और 2025 के लिए देश भर के 106 युवा कलाकारों को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किए।